एफपीआई ने की भारी पूंजी निकासी

अप्रैल में बाजार से 58,403 करोड़ रुपये की बिकवाली

घरेलू शेयर बाजार और निवेश माहौल पर दबाव बढ़ा

नई दिल्ली, 19 अप्रैल. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) ने अप्रैल 2026 में भारतीय पूंजी बाजार से भारी मात्रा में पूंजी की निकासी की है. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, इस महीने अब तक एफपीआई ने कुल 58,403 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है, जिससे घरेलू शेयर बाजार और निवेश माहौल पर दबाव बढ़ गया है.

यह लगातार दूसरा महीना है जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में बिकवाल की स्थिति में नजर आ रहे हैं.

आंकड़ों के मुताबिक, एफपीआई ने अप्रैल में सबसे ज्यादा निकासी इक्विटी से की है. उन्होंने शेयर बाजार से 43,419 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है. इसके अलावा, डेट (ऋण) बाजार में भी निवेशकों का रुख नकारात्मक रहा और वहां से 15,320 करोड़ रुपये की निकासी दर्ज की गई है. वहीं, हाइब्रिड उपकरणों से भी लगभग 13.5 करोड़ रुपये बाहर निकाले गए हैं.

हालांकि एक राहत की बात यह है कि म्यूचुअल फंड क्षेत्र में एफपीआई का रुख थोड़ा सकारात्मक रहा है, जहां उन्होंने 350 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया है. लेकिन यह राशि कुल निकासी के मुकाबले बेहद कम है.

> बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, अमेरिकी ब्याज दरों में बदलाव की आशंका, और डॉलर की मजबूती जैसे कारणों से एफपीआई भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं. इसके अलावा, मुनाफावसूली और वैश्विक पोर्टफोलियो री-बैलेंसिंग भी इस निकासी के प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं. इस भारी निकासी का असर घरेलू शेयर बाजार की अस्थिरता पर भी देखने को मिल सकता है. हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशक और रिटेल निवेशकों की भागीदारी बाजार को कुछ हद तक सपोर्ट दे रही है, लेकिन विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार में दबाव बनाए रखा है.

आईटी सेक्टर में 73,200 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी

नई दिल्ली, 19 अप्रैल. वर्ष 2026 की पहली तिमाही में आईटी सेक्टर के 73,200 से भी अधिक कर्मियों की नौकरियां चली गयी हैं. यह चिंताजनक आंकड़ा टेक इंडस्ट्री में छंटनी पर नजर रखने वाली वैश्विक साइट 'लेऑफ डॉट एफवाईआई' ने जारी किया है. आंकड़ों से पता चलता है कि पहली तिमाही के दौरान कुल 95 कंपनियां इस छंटनी प्रक्रिया में शामिल रहीं. इससे पहले के रुझानों पर गौर करें तो पता चलता है कि 2025 में भी बड़े स्तर पर नौकरियां गयी थीं और वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि कंपनियां अब भी लागत कम करने और एआई आधारित पुनर्गठन पर जोर दे रही हैं. एक के बाद एक छंटनी की घोषणा करने वाले प्रमुख नामों में 'द वॉल्ट डिज्नी कंपनी', 'मेटा प्लेटफॉर्म्स', 'स्नैप इंक' और 'ओरेकल कॉर्पोरेशन' शामिल थे.

एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 9.1% बढ़ा

चौथी तिमाही में मजबूत नतीजे, 192.2 अरब रुपये शुद्ध लाभ

नई दिल्ली, 19 अप्रैल. एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है. बैंक का एकल आधार पर शुद्ध लाभ 192.2 अरब रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.1 प्रतिशत अधिक है. यह वृद्धि ऐसे समय में आई है जब बैंकिंग सेक्टर में ब्याज दरों और क्रेडिट ग्रोथ को लेकर मिश्रित रुझान देखने को मिल रहे हैं.

बैंक के निदेशक मंडल ने शनिवार को हुई बैठक में न केवल वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी, बल्कि अंतिम लाभांश की भी घोषणा की. बैंक ने प्रत्येक एक रुपये अंकित मूल्य वाले शेयर पर 13 रुपये का अंतिम लाभांश देने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, वित्त वर्ष के दौरान पहले ही 2.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश दिया जा चुका है, जिससे कुल लाभांश 15.5 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच गया है.

तिमाही के दौरान बैंक का शुद्ध राजस्व भी 5 प्रतिशत बढ़कर 462.8 अरब रुपये हो गया है. पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो बैंक का शुद्ध लाभ 10.9 प्रतिशत बढ़कर 746.7 अरब रुपये और शुद्ध राजस्व 13.62 प्रतिशत बढ़कर 1,912.2 अरब रुपये तक पहुंच गया है. यह प्रदर्शन बैंक की स्थिर आय वृद्धि और मजबूत बैलेंस शीट को दर्शाता है.

> ऋण वितरण के मोर्चे पर भी बैंक ने अच्छी वृद्धि दर्ज की है. 31 मार्च 2026 तक बैंक का कुल बकाया ऋण 29.600 अरब रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है. इसमें खुदरा ऋण में 6.5 प्रतिशत, एसएमई (लघु एवं मध्यम उद्यम) ऋण में 17.2 प्रतिशत और थोक ऋण में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. साथ ही बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला है. सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घटकर 0.91 प्रतिशत रह गई है, जो पिछली तिमाही में 1.24 प्रतिशत थी. वहीं, शुद्ध एनपीए भी 0.42 प्रतिशत से घटकर 0.38 प्रतिशत पर आ गया है.

होर्मुज तनाव से भारत में एलपीजी खपत घटी

नई दिल्ली, 19 अप्रैल पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य पर संकट के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गहरा असर पड़ा है, जिसका सीधा प्रभाव भारत की रसोई गैस यानी एलपीजी खपत पर देखने को मिला है.

हालिया आंकड़ों के अनुसार देश में एलपीजी खपत में लगभग 13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जो न केवल अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता को दर्शाती है, बल्कि घरेलू स्तर पर बढ़ती महंगाई और आपूर्ति चुनौतियों की ओर भी संकेत करती है.

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका-ईरान टकराव के कारण होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से कच्चे तेल और गैस की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. यह जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार का एक अहम मार्ग है, जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस की ढुलाई होती है. इसके अवरुद्ध होने से अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल आया, जिसका असर भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर अधिक पड़ा है.

भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है. ऐसे में वैश्विक कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में बाधा ने घरेलू बाजार में कीमतों को प्रभावित किया है.

वड्डेपल्ली रामचंदर ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का किया दौरा

दौरे के दौरान उन्होंने कंपनी में अजा कर्मचारियों के हितों की समीक्षा की

बैठक में वेकोलि के निदेशक संदीप परांजपे ने आयोग का स्वागत किया

नागपुर, 19 अप्रैल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार के माननीय सदस्य वड्डेपल्ली रामचंदर ने दिनांक 18 अप्रैल 2026 को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) का आधिकारिक दौरा किया. इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान उन्होंने कंपनी में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के कल्याण, आरक्षण नीति के कार्यान्वयन और उनके हितों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की.

इस अवसर पर आयोग के निदेशक जी. सुनील कुमार बाबू भी उपस्थित रहे. बैठक में वेकोलि के निदेशक (तकनीकी/योजना एवं परियोजना) संदीप परांजपे ने आयोग का स्वागत किया और कंपनी की गतिविधियों से अवगत कराया.

> प्रबंधन ने आयोग को आश्वस्त किया कि वेकोलि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है. बैठक के अंत में आयोग ने वेकोलि द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और भविष्य के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. बैठक में श्री डी. के. चौधरी महाप्रबंधक (वित्त), डॉ श्री. नियोगी, प्रमुख चिकित्सा सेवा, महाप्रबंधक श्री एस. पी. तिवारी (सिविल वेलफेयर) भी उपस्थित थे.

बैठक के दौरान माननीय सदस्य वड्डेपल्ली रामचंदर ने वेकोलि में कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की.

निदेशक श्री जी. सुनील कुमार बाबू ने संबंधित अधिकारियों को संवैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

समीक्षा बैठक के दौरान महाप्रबंधक (मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध) ललित प्रकाश तिर्की एवं प्रबंधक (मानव संसाधन) सह संपर्क अधिकारी अतुल बन्सोड भी उपस्थित थे.

सीआईआई ने दिया राष्ट्रीय औद्योगिक भूमि बैंक बनाने का सुझाव

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने देश में उद्योगों के विकास को गति देने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक भूमि बैंक बनाने का सुझाव दिया है.

परिसंघ की रविवार को जारी रिपोर्ट में कहा इस बात पर जोर दिया गया है कि निवेश को तेज करने, परियोजनाओं में लगने वाले समय को कम करने और देश को एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए औद्योगिक भूमि तक कुशल और पारदर्शी पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है.

सीआईआई का कहना है कि विनिर्माण, अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स के लिए औद्योगिक भूमि एक बुनियादी संसाधन है. विभिन्न राज्यों में वर्तमान व्यवस्था खंडित प्रक्रियाओं, जटिल विनियमों, अस्पष्ट भूमि शीर्षक, कब्जा मिलने में देरी और आवंटित भूमि के कम उपयोग जैसी समस्याओं से ग्रस्त है. इनके कारण पूंजी लागत बढ़ती है, परियोजनाओं में देरी होती है, और विशेष रूप से छोटे तथा मझौले उद्योगों और बिल्कुल नयी परियोजनाओं के प्रति निवेशकों का विश्वास कमजोर होता है.

रिपोर्ट की एक प्रमुख सिफारिश एकीकृत और जीआईएस-सक्षम राष्ट्रीय औद्योगिक भूमि बैंक की स्थापना है जिससे भूमि की उपलब्धता, जोनिंग स्थिति, उपयोगिताओं, पर्यावरणीय बाधाओं और स्वामित्व की स्पष्टता पर तत्काल जानकारी प्राप्त हो सके. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और निवेश निर्णय तेज और बेहतर होंगे.

> सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि मेक इन इंडिया राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और आधुनिक लॉजिस्टिक्स के तहत देश की विनिर्माण महत्वाकांक्षाएं तब तक पूरी नहीं हो सकतीं, जब तक औद्योगिक भूमि सहज, पारदर्शी और निवेश के लिए तैयार न हो. रिपोर्ट में औद्योगिक भूमि के पूरे जीवनचक्र का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जिसमें भूमि की खोज और पहचान, आवेदन, आवंटन, भूमि उपयोग परिवर्तन, स्वामित्व, भौतिक कब्जा, आवंटन के बाद उपयोग आदि शामिल हैं.

चावल, दालों में तेजी; चीनी नरम

चावल की औसत कीमत 3,843 रुपये प्रति क्विंटल

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव बढ़ गये. चावल के साथ दालों में भी तेजी रही. चीनी के भाव टूट गये जबकि खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा.

सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 84 रुपये बढ़कर सप्ताहांत पर 3,843 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी. गेहूं की कीमत 2,770 रुपये प्रति क्विंटल पर लगभग स्थिर रही. आटा आठ रुपये सस्ता हुआ और 3,270 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया.

सप्ताह के दौरान उड़द दाल की औसत कीमत 49 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी. चना दाल 23 रुपये और मूंग दाल 22 रुपये मजबूत हुई. मसूर दाल नौ रुपये और तुअर दाल चार रुपये प्रति क्विंटल की साप्ताहिक बढ़त में रही.

बीते सप्ताह मूंगफली तेल 303 रुपये और पाम ऑयल 142 रुपये प्रति क्विंटल सस्ता हुआ. वनस्पति की कीमत 104 रुपये और सोया तेल की 76 रुपये बढ़ गयी. सरसों तेल 38 रुपये और सूरजमुखी तेल 22 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ.

मीठे के बाजार में बीते सप्ताह गुड़ का औसत भाव 26 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गया. वहीं, चीनी भी 20 रुपये सस्ती हुई.

आईसीआईसीआई बैंक को 13,702 करोड़ रुपये का तिमाही मुनाफा

मुंबई, 19 अप्रैल. निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 13,702 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ जो सालाना आधार पर 8.5 प्रतिशत अधिक है. बैंक ने शनिवार को वित्तीय परिणामों की घोषणा की. बैंक के निदेशक मंडल ने प्रति शेयर 12 रुपये के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है. तिमाही के दौरान बैंक को ब्याज से 22,979 करोड़ रुपये की शुद्ध आय हुई जो 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. शुल्क के रूप में उसने 6,779 करोड़ रुपये की कमाई की.

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट

नई दिल्ली, 19 अप्रैल सोना और चांदी के दामों में इस हफ्ते तेज गिरावट देखने को मिली है. बाजार के ताज़ा अपडेट के मुताबिक सोना अपने हालिया उच्च स्तर से करीब 48,000 रुपये सस्ता हो गया है, जबकि चांदी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और यह अपने हाई से लगभग 1.81 लाख रुपये तक नीचे आ गई है.

वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और निवेशकों की मुनाफावसूली को इस गिरावट का प्रमुख कारण माना जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग में कमी आने से भारतीय बाजार पर भी सीधा असर पड़ा है, जिससे 24 कैरेट सोने के दामों में लगातार नरमी देखने को मिल रही है.

विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में सोना-चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थीं, जिसके बाद अब बाजार में करेक्शन का दौर चल रहा है. निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर खरीदारी के बाद मुनाफा निकालना शुरू कर दिया है, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ा है.

घरेलू बाजार में ज्वैलर्स के अनुसार शादी-विवाह के सीजन से पहले आई यह गिरावट ग्राहकों के लिए राहत की खबर हो सकती है.

समाचार विशेष

जातीय समीकरण साध पाएगी भाजपा?

पटना/दिल्ली. बिहार में अब बीजेपी के सम्राट का राज शुरू हो गया है. सीएम सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती सिर्फ सरकार चलाने की नहीं, बल्कि बिहार के जटिल जातीय समीकरण पर मजबूत पकड़ बनाने की भी होगी.

2023 की जाति आधारित गणना के बाद राज्य का सामाजिक गणित पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुका है. इसी आधार पर आने वाले समय की राजनीति तय होती नजर आ रही है.

सम्राट चौधरी के बिहार का मुखिया बनने से बीजेपी का बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य तो पूरा हो गया है लेकिन इस पूरे राजनीतिक गणित के पीछे लक्ष्य और भी हैं.

बीजेपी का पारंपरिक आधार सवर्ण और अगड़ी जातियां रही है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में सिर्फ इसी आधार पर लंबे समय तक सत्ता में बने रहना आसान नहीं है. अब जब बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की भूमिका में दिख रही है, तो उसके फोसदी के आसपास है. अब तक इस सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह इन सामाजिक समूहो का एक साथ कैसे साधे. सम्राट को आगे करना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. ताकि लवकुश समीकरण को पुख्ता किया जा सके और इसके सहारे अन्य गैर-यादव ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और एससी वर्ग को अपने खेमे में किया जा सके.

जेडीयू को भी अपना वोट बैंक सेफ रखने की चुनौती- बिहार की राजनीति में लव-कुश (कुर्मी ने डिप्टी सीएम पद पर अपने दो वरिष्ठ और कुशवाहा) समीकरण का खास महत्व है. इनकी संयुक्त हिस्सेदारी 9 फीसदी के आसपास है. अब तक इस सामाजिक आधार पर नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी के जरिये बीजेपी इसमें सेंध लगाने की कोशिश में है.

> **सत्ता में टिके रहने का समीकरण**
>
> बीजेपी ने सम्राट को सीएम बनाकर यह संकेत देने की कोशिश की है कि वह बिहार में गैर-यादव ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महादलितों में भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना चाहती है. बिहार की सत्ता मे लंबे समय तक टिके रहने के लिए यही सामाजिक विस्तार अहम माना जाता है. 2023 की जाति आधारित गणना के मुताबिक, बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की आबादी 36.01 फीसदी है. अन्य पिछड़ा वर्ग 27.12 फीसदी, अनुसूचित जाति 19.65 फीसदी, सवर्ण 15.52 फीसदी और मुस्लिम आबादी 17.7 फीसदी है. आंकड़ों से साफ है कि बिहार में सबसे निर्णायक भूमिका ईबीसी और ओबीसी

मन्नारगुडी सीट पर इन नेताओं के बीच होगी कड़ी टक्कर

पिछले चुनाव के आंकड़े भी जान लीजिए

चेन्नई. अभी विधानसभा चुनावों का दौर चल रहा है. इसी महीने की 9 तारीख को 2 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में 1 चरण में विधानसभा के चुनाव हो गए. अब दो राज्यों के विधानसभा चुनाव बचे हैं जिसमें एक पश्चिम बंगाल और दूसरा राज्य तमिलनाडु है.

आने वाले 23 अप्रैल को तमिलनाडु में एक ही चरण में विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव होंगे और 4 मई को दूसरे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के साथ ही तमिलनाडु के भी नतीजे सामने आएंगे. तमिलनाडु के मन्नारगुडी सीट पर नेताओं के बीच में कड़ी टक्कर होने वाली है.

आपको बता दें कि मन्नारगुडी सीट तमिलनाडु का एक जनरल सीट है. इस सीट पर इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में आपको मुख्य टक्कर टीआरबी राजा (डीएमके) और एस. कामराज (एडीएमके) के बीच होने की उम्मीद है. वहीं, यूवीएम राजराजन (टीवीके) और आर भरथिसेल्वन (एनटीके) भी चुनावी मैदान में हैं, जिससे यह एक बहुकोणीय चुनावी जंग बन गई है.

> **पिछले चुनाव में क्या नतीजे आए थे?**
>
> अगर आपको साल 2021 के विधानसभा चुनावों की के नतीजे बताएं तो उस चुनाव में डीएमके के टीआरबी राजा ने 37,393 वोटों के अंतर से इस सीट पर जीत हासिल की थी. उन्हें 45.11 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 87,172 वोट मिले थे. उन्होंने एआईएडीएमके के राजमनिक्कम सिवा को हराया था, जिन्हें 49,779 वोट (25.76 प्रतिशत) मिले थे.

नीतीश कुमार का 'दिल्ली प्लान' तैयार

पटना. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की तैयारी पूरी हो गई है.

उन्हें दिल्ली के सुनहरी बाग में बंगला नंबर 9 आवंटित किया गया है. टाइप-8 कैटेगरी का यह एक बेहद आलीशान बंगला है. यह कोई साधारण बंगला नहीं है. यह तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है. दिल्ली में सांसद नीतीश कुमार के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. इसके पहले नीतीश कुमार का आवास 6, कामराज लेन पर स्थित था.

दिल्ली के जिस इलाके में पूर्व सीएम नीतीश कुमार को बंगला आवंटित किया गया है. वह दिल्ली का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है. यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जैसे देश के प्रमुख नेता रहते है. आपको बता दें कि, लुटियंस दिल्ली के सरकारी आवासों को टाइप-1 से लेकर टाइप-8 में वर्गीकृत किया गया है.

विशेष | हर बार चेहरा बदलने वाली जनता का इस बार क्या है मिजाज

कूचबिहार दक्षिण पर किसका होगा राज?

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर पर बसे कूचबिहार जिले की हवाओं में इस समय चुनावी सरगर्मी घुली हुई है. कभी राजघराने की शान रहा यह इलाका आज लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की तैयारी कर रहा है. कूचबिहार दक्षिण विधानसभा सीट केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह बंगाल की उस बदलती राजनीति का दर्पण है जहां मतदाताओं ने कभी भी किसी एक विचारधारा को स्थायी जगह नहीं दी है.

23 अप्रैल को जब यहां की जनता वोट डालने निकलेगी, तो उनके मन में बीते सालों का हिसाब और भविष्य की उम्मीदें दोनों होंगी. इस औद्योगिक और कृषि प्रधान क्षेत्र में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, यह सवाल आज चाय की दुकानों से लेकर बड़े राजनीतिक दफ्तरों तक में गूंज रहा है. इस क्षेत्र की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां के लोग बदलाव के शौकीन रहे हैं. साल 2011 से लेकर अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो हर विधानसभा चुनाव में जनता ने एक नया चेहरा और नई पार्टी को मौका दिया है. 2011 में जब बंगाल में परिवर्तन की लहर थी, तब यहां से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के अक्षय ठाकुर ने जीत दर्ज की थी. पांच साल बाद 2016 में जनता का मन बदला और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के मिहिर गोस्वामी को अपनी पसंद बनाया. लेकिन 2021 के चुनाव ने सबको हैरान कर दिया जब भाजपा के निखिल रंजन दे ने तृणमूल के गढ़ में सेंध लगाते हुए करीब वोटों के अंतर से जीत हासिल की. यह उतार-चढ़ाव दिखाता है कि यहां की जनता नेता को हल्के में नहीं लेती और काम के आधार पर अपना फैसला बदल देती है. कूचबिहार दक्षिण में अनुसूचित जाति और मुस्लिम समुदाय की यहां बड़ी आबादी है, जो किसी भी दल की जीत और हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

> **क्या भाजपा बचा पाएगी अपना गढ़**
>
> अब सबकी निगाहें अप्रैल में होने वाले मतदान और 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं. पिछले चुनाव में भाजपा ने 46.8 प्रतिशत वोट हासिल कर अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी 44 प्रतिशत वोटों के साथ बहुत पीछे नहीं थी. वहीं फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस का गठबंधन अब काफी कमजोर पड़ चुका है और उनकी वोट हिस्सेदारी सिमटकर महज चार-पांच प्रतिशत रह गई है. ऐसे में मुकाबला सीधे तौर पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच ही सिमटता नजर आ रहा है. मतदाता इस बार किसी पार्टी की विचारधारा को चुनेंगे या फिर स्थानीय विकास के दावों पर मुहर लगाएंगे, यह देखना वाकई रोमांचक होगा.